बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा

वर्ष 2012–13

सरकारी विभागों से प्राप्त जानकारी पर आधारित

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम,
जयपुर–302005
फोन/फैक्स – 0141–2385254
E-mail: info@barcjaipur.org
Web: www.barcjaipur.org

वर्ष 2011–12 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा

इस वर्ष मार्च में राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट पेश करेगी। सरकार द्वारा पेश किया गया बजट सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है 'बजट भाषण' जिसे मुख्यमंत्री राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते विधानसभा में पढ़कर सुनाते हैं। चुंकि बजट भाषण आम जनता तथा मिड़िया को लक्ष्य करके पढ़ा जाता है इसलिये इसमें कई महत्वपूर्ण तथा जनता की भलाई के लिये किये जाने वाले कार्यों की घोषणा की जाती है। पिछले वर्ष मार्च में राज्य सरकार ने बजट भाषण में कई घोषाणाएं की थीं जिन्हे वित्तीय वर्ष 2012–13 में लागु किया जाना अपेक्षित था दिसम्बर 2012 में इन घोषणाओं के 9 महिने बाद बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र ने कुछ चुने हुए विभागों से संबधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जानने का प्रयास किया।

इसके लिए कुल 15 विभागों पशुपालन, वन एवं पर्यावरण, नगरीय विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, कृषि, अल्पसंख्यक मामलात, जनजाति क्षेत्रीय विकास, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, श्रम कल्याण तथा उद्योग विभाग से इस संबंध में सूचनाएं प्राप्त करने की कोशिश की गई। उपरोक्त विभागों से बजट घोषणाओं की स्थिति जानने के लिए सभी विभागों से उनके बजट घोषणाओं पर प्रगति की जानकारी चाही गई। बजट घोषणाएं 2012–13 की प्रगति की नवीनतम जानकारी केवल पंचायती राज एवं जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध थी जबकि पशुपालन तथा शिक्षा विभाग द्वारा वेबसाईट पर बजट घोषणाओं की एक या दो माह पुरानी जानकारी का ब्यौरा उपलब्ध रखा गया था। अन्य विभागों के वेबसाईट पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इन विभागों से बजट घोषणाओं की प्रगति की सूचना चाहे जाने पर, सूचना का अधिकार कानून का उपयोग किए बिना, 15 में से केवल 14 विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई गई। अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा बार बार संपर्क करने पर भी बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई।

इस रिर्पोट में बार्क के प्रयासों से बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी विभागवार रूप में दी जा रही है। नीचे दी गई सारणी से पता चलता है कि जिन विभागों से संबंधित घोषणाओं की जानकारी मिली है उन्होंने भी पूरी जानकारी नहीं देकर कुछ घोषणााओं से संबंधित जानकारी ही दी है। जैसे कृषि विभाग से संबंधित 10 घोषणाएं की गईं लेकिन विभाग द्वारा केवल 8 घोषणाओं की प्रगति की सूचना ही दी गई। श्रम कल्याण विभाग द्वारा 8 घोषणाओं में से केवल 3 घोषणाओं की सूचना उपलब्ध करवाई गई। इसी तरह नगरीय विकास एवं ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग द्वारा भी सभी घोषणाओं की प्रगति की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

विभाग बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जनता को बताना आवश्यक नहीं समझते तथा काफी भागदौड़ के बाद भी आधी अधूरी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। जिसमें केवल फाइलों के प्राप्त होने तथा भेजे जाने की तिथी एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने की तिथी का विवरण होता है इस जानकारी के आधार पर भौतिक प्रगति का आंकलन कर पाना मुश्किल होता है।

सरकारी विभागों द्वारा बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी नहीं देने या अधूरी जानकारी देने के कारण संभवतः अधिकांश घोषणाओं का लागु नहीं हो पाना हो सकता है। कुल 14 विभागों से प्राप्त बजट घोषणाओं की अधूरी जानकारी से मुख्यतः यह पता चलता है कि उक्त घोषणाओं को लागु करने के आदेश जारी हो चुके हैं तथा कार्यक्रम एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। परन्तु वास्तव में धरातल पर कितना क्रियान्वयन हुआ इसकी जानकारी कम ही मामलों में दी गई है।

वर्ष 2012–13 की बजट घोषणाओं की प्रगति

कृषि विभाग		
कृषि से संबंधित कुल 10 घोषणाएं की गई थीं लेकिन विभाग द्वारा केवल 8 घोषणाओं की प्रगति की सूचना उपलब्ध करवाई गई।		
	घोषणा	**प्रगति (01 दिसम्बर 2012)**
1	कृषि विषय की उच्च माध्यमिक कक्षाओं की छात्राओं को 5 हजार, बीएससी एवं एमएससी को 10 हजार एवं पीएचडी को 15 हजार रू. प्रोत्साहन राशि देने की बात कही।	सभी वर्गों के राशि हस्तांतरण के आदेश जारी किये जा चुके हैं 15 दिसम्बर तक छात्राओं के खाते में प्रोत्साहन राशि जमा करवाने की बात कही गई है।
2	जोधपुर तथा सुमेरपुर में कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय खोले जायेंगे।	दोनों महाविद्यालयों में कर्मचारियों की पदस्थापन पर नियुक्ति कर दी गई है तथा शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
3	फार्म पोण्ड निर्माण पर अनुदान 60 हजार रू. एवं डिग्गी निर्माण पर अनुदान 3 लाख रू. करने की बात कही गई।	24 अप्रेल 2012 को अनुदान राशि बढाने से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिये गये।
4	आगामी वर्ष 10 हजार फार्म पोण्ड्स व 5 हजार डिग्गीयां बनाने की बात कही गई।	अब तक 4260 फार्म पोण्ड्स का एवं 595 डिग्गीयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
5	बांसवाडा एवं डूंगरपुर में मक्का के हाइब्रिज बीज हेतू बीज ग्राम योजना का संचालन किया जायेगा।	कृषक एवं गांव का चयन किया जा चुका है तथा मक्का बुवाई का कार्य किया जा रहा है।
6	आगामी वर्ष कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों के 750 नवीन पद सृजित किये जायेंगे।	वर्तमान समय तक कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकी है।
7	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मृदा सुधार टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा।	12 जून 2012 को मृदा टास्क फोर्स का निर्माण किया जा चुका है।
8	प्रदेश में 10 नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जायेंगे।	सभी 10 कृषि विज्ञान केन्द्र प्रारम्भ किये जा चुके हैं तथा केन्द्रों में पदों पर नियुक्ति की जानी अभी बाकी है।
पशु पालन विभाग		
पशु पालन से संबंधित 4 घोषणाएं की गई थीं विभाग द्वारा सभी घोषणाओं की प्रगति सूचना उपलब्ध करवाई गई।		
	घोषणा	**प्रगति (05 नवम्बर 2012)**
1	राज्य के राजकीय पशु चिकित्सालयों में निशुल्क दवा योजना लागू करने की बात कही गई।	पशुधन निशुल्क दवा योजना का क्रियान्वयन 15 अगस्त 2012 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

2	राज्य में 400 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रारम्भ किये जायेंगे।	125 उपकेन्द्र खोलने के प्रशासनिक आदेश जारी हो चुके है लेकिन संचालन प्रारम्भ होना अभी बाकी है।
3	200 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।	60 उपकेन्द्रों को क्रमोन्नत किया जा चुका हैं लेकिन 140 उपकेन्द्रों को क्रमोन्नत किया जना अभी बाकी हैं।
4	जोधपुर में पशुपालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी।	प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु टेण्डर प्रक्रिया जारी है अभी तक प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
वन विभाग		
वन विभाग से संबंधित 5 घोषणाएं की गई थीं विभाग द्वारा 4 घोषणाओं की प्रगति सूचना उपलब्ध करवाई गई।		
घोषणा		**प्रगति (05 दिसम्बर 2012)**
1	नाबार्ड के सहयोग से राज्य के 17 जिलों में 988 करोड़ की परियोजना से सघन वृक्षारोपण एवं जलग्रहण क्षेत्र विकसित किया जायेगा।	वनीकरण के माध्यम से जलग्रहण विकास की परियोजना की स्वीकृत हो चुकी है लेकिन योजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन अभी बाकी है।
2	400 हैक्टेयर क्षेत्र में सेवण घास विकसित करने हेतु योजना संचालित की जायेगी।	400 हैक्टेयर क्षेत्र में फेन्सिंग कार्य, घास बीज बुवाई व घास स्लिप प्लान्टिंग कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है।
3	सरिस्का बाघ परियोजना के समीपस्थ क्षेत्रों में 5 हजार गैस कनेक्शन तथा हर कनेक्शन पर 1,800 रू. का अनुदान दिया जायेगा।	826 गैस कनेक्शन की राशि गैस एंजेसी को दी जा चुकी है लेकिन गैस एजेंसी ने कनेक्शन आवंटित नहीं किये हैं।
4	राज्य में 5 स्थानों पर चोटग्रस्त वन्यजीवों के उपचार के लिये रेसक्यू सेंटर खोले जायेंगे।	2 रेसक्यू सेंटर का कार्य प्रगतिरत है जबकि 3 रेसक्यू सेंटर का कार्य प्रारम्भ किया जाना अभी शेष है।
पंचायती राज विभाग		
पंचायती राज से संबंधित कुल 9 घोषणाएं की गई थीं विभाग द्वारा सभी 9 घोषणाओं की प्रगति की सूचना उपलब्ध करवाई गई।		
घोषणा		**प्रगति (05 दिसम्बर 2012)**
1	पंचायतों पर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के विस्तार के प्रथम चरण में 3 हजार ग्राम पंचायतों एवं सभी 249 पंचायत समितियों में विस्तार कार्य करवाया जायेगा।	188 ब्लॉक पंचायत एवं 413 ग्राम पंचायत के कार्यों की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है लेकिन किसी भी पंचायत में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
2	पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न संवर्गों के 23 हजार से	22828 पदों पर वित्त विभाग से स्वीकृति हुई है। 265 पंचायत प्रसार अधिकारी के पद सृजित हो चुके हैं।

	अधिक नवीन पद सृजित किये जायेंगे।	
3	राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक एक कम्प्यूटर उपलब्ध करवाया जायेगा।	आयोजना एवं वित्त विभाग की सहमति हो गई है लेकिन पंचायतों को कम्प्यूटर उपलब्ध्ध नहीं हुये हैं।
4	कोटा, भरतपुर एवं बीकानेर में 2 करोड़ की लागत से नवीन पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा।	प्रशिक्षण केन्द्र हेतु भूमि चिन्हीकरण हो चुका है लेकिन भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
5	राज्य में 115 ग्राम पंचायतों के लिये भवन निर्माण एवं 307 पंचायतों के भवनों का जीर्णोद्वार करवाया जायेगा।	ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण एवं जीर्णोद्वार के कार्य हेतु राशि जारी हो चुकी है लेकिन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
6	जिला परिषदों में 25 लाख रू. की लागत से आम जन के लिये बैठक एवं प्रशिक्षण स्थल का निर्माण करवाया जायेगा।	सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है।
7	संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत 3,300 विद्यालयों एवं 5 हजार आंगनबाडीयों में टॉयलेट्स बनाये जायेंगे।	1772 स्कूल शौचालय एवं 149 आंगनबाडी शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है।
8	स्वजलधारा, जनता जल, सैक्टर रिफोर्म एवं पनघट आदि योजनाओं के संचालन के लिये पंचायतों को 50 करोड रू. उपलब्ध करवाये जायेंगे।	50 में से 15.54 करोड़ रू. देने पर वित्तीय स्वीकृति हो गई है राशि आवंटन संभव नहीं हो सका है।
9	जलग्रहण एवं भू संरक्षण हेतु 202 पंचायत समिति में 604 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनसे 34.84 लाख हैक्टेयर बारानी क्षेत्र उपचारित किया जायेगा।	वर्ष 2009–10 में केन्द्र सरकार द्वारा 604 परियोजनाएं 4 से 6 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत की गईं विभाग द्वारा निश्चित अवधि में तय लक्ष्य पूर्ण करने की बात कही गई है।
ग्रामीण विकास विभाग **ग्रामीण विकास से संबंधित कुल 6 घोषणाएं की गई थीं विभाग द्वारा सभी 6 घोषणाओं की प्रगति की सूचना उपलब्ध करवाई गई।**		
	घोषणा	**प्रगति (05 दिसम्बर 2012)**
1	राज्य के 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को, 3 वर्ष में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना द्वारा निशुल्क आवास उपलब्ध करवाये जायेंगे।	2011–12 में 437596 आवास निर्माण के विरूद्ध 183356 आवास का कार्य पूर्ण कराया गया। 2012–13 में 291000 आवास निर्माण के विरूद्ध प्रगति की सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई।
2	राज्य में राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं एमपावर योजना द्वारा लगभग 3 लाख व्यक्तियों का लाभान्वित किया जायेगा।	वर्ष 2012–13 में एमपावर योजना के अंर्तगत 16788 व्यक्तियों को तथा आर.आर.एल.पी. में वर्ष 2012–13 में 4210 व्यक्तियों को लाभांवित किया गया। एन.आर.एल.एम. की कार्य योजना को भारत सरकार

		द्वारा अनुमोदित कर लिया गया है।
3	विश्व बैंक की 10 करोड़ लागत की योजना से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु नवाचार के योग्य प्रस्तावों का प्रायोगिक तौर पर क्रियान्वयन किया जायेगा	ग्रामीण क्षेत्र नवाचार के योग्य प्रस्तावों की विभाग द्वारा सूची बनाई जाकर विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई है।
4	डांग एवं मगरा विकास योजनाओं के लिये 20–20 करोड़ तथा मेवात विकास योजना के लिये 25 करोड़ की राशि प्रावधान करने की बात कही।	सभी योजनाओं की बजट राशि उनके विकास बोर्ड को जारी कर दी गई है।
5	राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अंशदान से संचालित ग्रामीण जनभागीदारी योजना हेतु इस वर्ष 35 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया।	ग्रामीण जनभागीदारी योजना हेतु इस वर्ष 35 करोड की राशि का बजट जारी कर दिया गया है।
6	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि को बढाकर 2 करोड करने की बात कही गई।	4 जून 2012 को योजना की राशि 2 करोड़ करने के आदेश जारी हो चुके हैं।
नगरीय विकास विभाग		
नगरीय विकास के संबंध में कुल 13 घोषणाएं की गई थीं लेकिन विभाग द्वारा केवल 3 घोषणाओं की प्रगति की सूचना ही उपलब्ध करवाई गई।		
	घोषणा	**प्रगति (01 दिसम्बर 2012)**
1	राज्य में मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना द्वारा प्रति वर्ष 1 लाख शहरी बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने हेतु 50000 की सहायता देने की बात कही गई।	30/8/2012 से योजना प्रारम्भ हो गई है तथा 14 नगर निकायों से 10088 लाभार्थीयों की सूची प्राप्त हो चुकी है। लेकिन आवास का आवंटन प्रारम्भ नहीं हुआ है।
3	किशनगढ, मकराना एवं राजसमंद के खदान क्षेत्रों में 5–5 करोड रू. के बहुउद्देशीय विकास के कार्य करवाये जायेंगे।	उक्त तीनों क्षेत्रों को राशि जारी करने के लिये प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाये गये हैं।
4	सालावास और बासनी बेंदा में कुल 90 एमएलडी क्षमता के दो STP स्थापित करने की बात कही गई।	वित्त विभाग 24 करोड़ की राशि हस्तान्तरण की स्वीकृति से प्राप्त हो चुकी है। कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
5	32 में 6 आर.ओ.बी. का कार्य पूर्ण कर लिया गया है शेष 26 आर.ओ.बी. का कार्य जून से प्रारम्भ करने की बात कही।	इसमें से 24 आरओबी का कार्य प्रगति पर है।
6	वर्ष 2012–13 में 4 जिलों में 10 आर.ओ.बी एवं आर.यू.बी. का निर्माण प्रारम्भ करवाया जायेगा इसके अलावा 10 आर. ओ.बी. एवं आर.यू.बी. का निर्माण भी शुरू करवाया जायेगा।	वर्तमान समय तक सभी 10 आर.ओ.बी. एवं आर.यू.बी. में से किसी का कार्य भी प्रारम्भ नहीं हो सका है।
7	भरतपुर मथुरा रोड पर स्थित ब्रिज का पुर्ननिर्माण करवाया जायेगा।	निविदा की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

8	आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा चितौडगढ में ग्राम चंदेरिया के पास आर.यू.बी. का निर्माण तथा जयमार्ग अलवर के आर.ओ.बी. को 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित किया जायेगा।	दोनों कार्यों के कार्यादेश हो चुके हैं तथा कार्य प्रारम्भ हो चुका है।
10	सभी जिला मुख्यालयों के नगरीय निकायों को नगर परिषद का दर्जा देने की दृष्टि से घोषणा।	दिनांक 30.04.2012 जिला मुख्यालय की 17 नगर पालिकाओं को नगर परिषद घोषित कर दिया गया है।
11	RUIDP के तृतीय चरण के अंतर्गत एशियन डवलपमेंट बैंक से प्राप्त 1250 करोड़ रू. के ऋण पर परियोजनागत कार्यों का संचालन किया जायेगा।	परियोजना हेतु 19 शहरों का चयन हो गया है, इसमें सम्मिलित होने वाले सेक्टरों का चयन किया जा रहा है।
12	बड़े शहरों में स्ट्रीट लाइटिंग हेतु कम खपत वाली एलईडी लाइटों का उपयोग किये जाने की योजना बनाई जायेगी।	IFC of Word Bank Group से एमओयू किया गया है लेकिन योजना का क्रियान्वयन शुरू नहीं हो सका है।
13	जोधपुर व कोटा में 73 बसें क्रय कर संचालित की जायेंगी।	जोधपुर हेतु बसें क्रय करने ओदश जारी किए जा चुके है। कोटा हेतु आदेश दिया जाना बाकी है।
14	स्थानीय निकायों, नगर विकास न्यास, राजस्थान आवासन मण्डल की तरफ बकाया लीज राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेंगी	बकाया राशि पर छूट की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
15	राज्य में 1265 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग्स पर आर.यू.बी बनाने के कार्य रेलवे द्वारा करवाये जायेंगे।	आर.यू.बी. निर्माण हेतु जिला कलेक्टरों से 691 अनापति पत्र प्राप्त हो चुके है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ होना अभी बाकी है।
16	प्रदेश में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में 2 वर्षो की अवधि में 20,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की जायेगी।	नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है लेकिन भर्ती पूर्ण होना अभी बाकी है।

महिला एवं बाल विकास विभाग

महिला एवं बाल विकास से संबंधित कुल 3 मुख्य व अन्य घोषणाएं की गईं विभाग द्वारा सभी घोषणाओं की प्रगति की सूचना उपलब्ध करवाई गई।

	घोषणा	प्रगति (05 दिसम्बर 2012)
1	महिलाओं को शोषण एवं उत्पीडन से बचाने के लिये महिला हैल्पलाईन प्रारम्भ की जायेगी।	राज्य महिला आयोग के तत्वाधान में हेल्पलाईन को प्रारम्भ कर दिया गया है।
2	महिला अधिकारिता निदेशालय में एक महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।	विशेष महिला प्रकोष्ठ द्वारा 1 जुलाई 2012 से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
3	राज्य में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण एवं उत्पादित माल के विपणन में सहयोग के लिये हर ब्लॉक स्तर पर धन लक्ष्मी महिला समृद्दि केन्द्र खोला जायेगा।	राज्य के 3 जिलों में धन लक्ष्मी महिला समृद्दि केन्द्र खोला जा चुका है शेष 30 जिलों में केन्द्र का संचालन अभी बाकी है।

4	महिला एस.एच.जी. द्वारा निर्मित सामग्री की सरकारी खरीद में प्राथमिकता के लिये नियमों में प्रावधान किया जायेगा।	9 जुलाई 2012 को जी.एफ.एण्ड ए.आर. में संशोधन हेतु आदेश जारी किये जा चुके हैं।
5	आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन एवं आशा सहयोगिनीयों का मानदेय 10 प्रतिशत बढाया जायेगा।	आंगनबाडी के उक्त सभी कर्मियों के मानदेय में बढोतरी के आदेश मई माह में जारी किये जा चुके है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग		
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से संबंधित कुल 6 मुख्य एवं अन्य घोषणाएं की गई थीं विभाग द्वारा सभी घोषणाओं की प्रगति सूचना उपलब्ध करवाई गई।		
घोषणा		**प्रगति (05 दिसम्बर 2012)**
1	राज्य के 5 जिलों में स्थित मानसिक विमंदित गृहों की क्षमता 50 से बढाकर 100 की जायेगी	5 में से 3 जिलों में पुर्नवास गृहों की क्षमता बढाने पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है।
2	राज्य के 13 जिलों में 50 की क्षमता वाले नये विमंदित गृह प्रारम्भ किये जायेंगे।	सभी जिलों से प्रस्ताव लिये गये हैं। किसी भी जिले में विमंदित गृह का संचालन प्रारम्भ नहीं हो सका है।
3	राज्य के 6 जिलों में नये वृद्धाश्रम प्रारम्भ किये जायेंगे।	2 जिलों में भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ है शेष जिलों में भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन हो पाया है।
4	राज्य में 8 वर्ष से कम आयु के निशक्त जनों को भी 250 रू. पेंशन के रूप में स्वीकृत की जायेगी।	18 जुलाई 2012 को 250 रू. पेंशन देने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।
5	पोलियों करेक्शन की राशि बढाकार 3 हजार से 5 हजार की जायेगी।	24 अप्रेल 2012 को पोलियों करेक्शन की राशि बढाने के आदेश जारी हो चुके हैं।
6	एचआईवी, एड्स से ग्रसित बच्चों के लिये 50 की क्षमता वाले किशोरगृह संचालित किये जायेंगे।	किशोरगृह हेतु जयपुर व जोधपुर में संस्थाओं का चयन हो चुका है लेकिन संचालन प्रारम्भ नहीं हो सका है।
7	राज्य के प्रत्येक जिले में विशेष योग्यजनों के लिये एक विशेष विद्यालय संचालित करने की बात कही गई।	सभी जिलों में संस्थाओं का चयन किया जा रहा हैं लेकिन विद्यालय का संचालन कहीं प्रारम्भ नहीं हुआ है।
8	राज्य में 1 हजार विशेष योग्यजनों को मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल निशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी।	20/10/12 को 50 मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण हुआ हैं शेष 950 का वितरण होना बाकी है।
9	राज्य में बेसहारा व्यक्तियों को सहारा देने हेतु निराश्रित संबल योजना प्रारम्भ करने की बात कही गई।	9 सितम्बर 2012 को सभी जिलों को योजना के दिशा निर्देश एवं बजट आवंटित कर दिया गया है।

10	राज्य में अनुसूचित जाति की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले प्रदेश के 100 गांवो को संबल बनाने हेतु समग्र विकास के कार्य करवाये जायेंगे।	100 गांवों का चयन कर उनकी राशि जिला परिषदों के पी.डी.खातों में जारी कर दी गई है। ग्राम विकास के लिये कार्य योजना तैयार की जा रही है।
11	अनुसूचित जाति के छात्रावासों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को गणित, विज्ञान एवं अग्रेजी की शिक्षा कम्प्यूटर सीडी एवं इंटरनेट के माध्यम से पढाया जायेगा।	अनुसूचित जाति के छात्रों को कम्प्यूटर सीडी एवं इंटरनेट के माध्यम से पढाने के लिये पाठ्य सामग्री का चयन किया जा रहा है।
12	जयपुर शहर में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये एक कॉलेज स्तर का छात्रावास निर्माण करवाया जायेगा।	भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित की गई है लेकिन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
13	जयपुर शहर में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिये एक कॉलेज स्तर के 2 छात्रावासों का निर्माण करवाया जायेगा।	भवन निर्माण हेतु 2 स्थानों पर भूमि चिन्हित की गई है लेकिन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
14	राज्य के 7 जिलों में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिये कॉलेज स्तर के एक एक छात्रावास का निर्माण करवाया जायेगा।	6 जिलों में छात्रावास निर्माण हेतु भूमि चिन्हित की गई है लेकिन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
15	आगामी वर्ष में 50–50 की क्षमता वाले अनुसूचित जाति के उपरोक्त 10 छात्रावासों का निर्माण करवाया जायेगा।	केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होने पर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया जायेगा।
16	राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा अनुसूचित जाति के 30 हजार व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत करवाया जायेगा।	36956 आवेदनो के विरूद्ध 4917 आवेदकों को ऋण वितरण किया जा चुका है।
17	राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा विभिन योजनाओं के अंतर्गत 5 हजार व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत करवाया जायेगा।	इस वर्ष 893 आवेदकों हेतु 552 लाख रू. की वित्तीय स्वीकृति हुई है। लेकिन ऋण प्राप्त करने वाले आवेदकों की संख्या उपलब्ध नहीं करवाई है।
18	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 50 छात्र एवं छात्राओं को जयपुर एवं कोटा में इंजिनियरिंग एवं मेडिकल परीक्षा की तैयारी के लिये कोचिंग की सुविधा दी जायेगी।	अभी तक कुल कुल 123 छात्रों के आवेदन प्राप्त हुये हैं तथा संस्थाओं से प्रस्ताव लिये जा रहे हैं। विभाग द्वारा लाभार्थियों की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई।
19	अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के एसएससी एवं युपीएससी में चयनित विद्यार्थियों के लिये मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु जयपुर में छात्रावास एवं कोचिंग की सुविधा दी जायेगी।	योजना हेतु बजट आवंटन किया जा चुका है विभाग द्वारा लाभार्थियों की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई।
20	अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल अभ्यर्थियों को भी अनुप्रति योजना में शामिल करने की बात कही गई।	योजना के संचालन हेतु नवीन दिशा निर्देश दिनांक 31 जुलाई 2012 को जारी किये जा चुके हैं।

21	गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2 लाख तक आय वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को भी अनुप्रति योजना का लाभ दिया जायेगा।	योजना के संचालन हेतु नवीन दिशा निर्देश दिनांक 31 जुलाई 2012 को जारी किये जा चुके हैं।
21	वर्तमान वर्ष में देवनारायण योजना अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं पर 136 करोड रू. खर्च का प्रावधान किया गया।	देवनारायण योजनांतर्गत विभिन्न योजनाओं की बजट राशि आवंटित की जा चुकी है तथा विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
22	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिये विभिन्न स्तर के 848 पद सृजित किये जायेंगे।	विभाग में कुल 31 पदों (वित्तीय सलाहकार के 3, सूचना सहायक के 14, कनिष्ठ लिपिक के 12 एवं चतुर्थ श्रेणी के 2 पदों) पर पदस्थापन किया जा चुका है।
23	ऐसे विशेष योग्यजन व्यक्ति जो स्वयं या जिनके माता पिता आयकर नहीं देते हैं वे सब कृत्रिम अंग एवं उपकरण के पात्र माने जायेंगे।	कृत्रिम अंग हेतु आय सीमा बढ़ाने के आदेश 16 मई 2012 को किये जा चुके हैं।
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग		
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के संबंध में 6 मुख्य व अन्य कई घोषणायें की गई थीं विभाग द्वारा सभी घोषणाओं की सूचना उपलब्ध करवाई गई।		
	घोषणा	**प्रगति (05 दिसम्बर 2012)**
1	प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में 175 मां–बाडी केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।	मां–बाडी केन्द्रों के लिये 396.55 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है एवं सभी केन्द्र 2–7–2012 से प्रारंभ कर दिये गये हैं।
2	कथोडी बस्तियों में 10 मां–बाडी केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।	मां–बाडी केन्द्रों के लिये 24.80 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है एवं सभी केन्द्र 2–7–2012 से प्रारंभ कर दिये गये हैं।
3	जनजाति छात्राओं के लिये बारां में बहुउद्देश्यीय छात्रावासों का निर्माण करवाया जायेगा।	छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन एवं 250 लाख रू. की स्वीकृति हो चुकी है। विभाग द्वारा भौतिक प्रगति की जानकारी नहीं उपलब्ध करवाई गई।
4	जनजाति छात्रों के लिये उदयपुर एवं कोटा में बहुउद्देश्यीय छात्रावासों का निर्माण करवाया जायेगा।	छात्रावास हेतु भूमि आवंटन एवं 250 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। विभाग द्वारा भौतिक प्रगति की जानकारी नहीं उपलब्ध करवाई गई।
5	अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम तथा राजस्थान क्षैत्रिय विकास सहकारी संघ के माध्यम से जनजाति के 6 हजार युवाओं को स्वरोजगार हेतु 10 हजार रु. तक का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।	स्वरोजगार हेतु अनुदान के लिये 106.90 लाख रु. व्यय करके 1069 व्यक्तियों को लाभांवित किया जा चुका है।

6	बांसवाडा स्थित मानगढ धाम में आजादी के लिये शहीद हुये 1500 लागों की याद में एक स्मारक बनाया जायेगा।	स्मारक निर्माण हेतु 5–09–2012 को वित्तीय स्वीकृति जारी कर राशि आवंटित कर दी गयी है। लेकिन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
7	सिरोही जिले के भामाणा गांव में शहीद हुए आदिवासियों की याद में एक स्मारक बनाने की बात कही गई।	दिनांक 21–11–2012 को वित्तीय वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है लेकिन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
8	बेणेश्वर, मानगढ धाम, घोटिया आंबा एवं भीमाणा के मेलों में जनजाति शिल्पकारों द्वारा निर्मित कलाकृतियों के प्रदर्शन व विपणन की व्यवस्था की जायेगी।	दिनांक 26–06–2012 को बेणेश्वर धाम हेतु 200 लाख तथा प्रत्येक के लिये 100 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
9	आदिवासी क्षेत्र के परिवारों को घरेलू सौर उर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिये 75 प्रतिशत अनुदान देकर 3 हजार परिवारों को लाभांवित किया जायगा।	12–06–2012 को 150 लाख रू. की वित्तीय स्वीकृति के जारी हो चुकी है। विभाग द्वारा लाभांवितों की संख्या का विवरण नहीं दिया गया।

शिक्षा विभाग

शिक्षा के संबंध में कुल 11 घोषणाएं की गई थीं लेकिन विभाग द्वारा केवल 5 घोषणाओं की प्रगति की सूचना ही उपलब्ध करवाई गई।

	घोषणा	प्रगति (05 नवम्बर 2012)
1	आगामी वर्ष में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती करने की बात कही गई।	6500 वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है।
2	उर्दू विषय में 100 स्कूल व्याख्याताओं, 200 वरिष्ठ अध्यापकों एवं 500 तृतीय श्रेणी शिक्षकों को नियुक्ति दी जायेगी।	सभी पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति होना बाकी है।
3	कल्प योजना के अंतर्गत 1 हजार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्युटर एवं 12 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित किये जायेंगे।	विभाग द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई।
4	राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना में 10वीं एवं 12वीं में मेरिट के अनुसार प्रथम 10–10 हजार बालक बालिकाओं को लैपटॉप तथा 8वीं में प्रथम आने वाले विद्यार्थीयों को लर्निंग लैपटाप्स पुरस्कार के रूप में दिये जायेंगे।	क्रय समिति एवं तकनीकी समिति का गठन कर लिया गया है तथा अतिरिक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
5	अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिये जोधपुर व कोटा में एक आवासीय विद्यालय स्थापित किये जायेंगे।	विभाग द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई।
6	आगामी वर्ष में 1 हजार नये प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं	विभाग द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई।

	600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की बात कही गई।	
7	राज्य की 79 ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की बात कही गई।	77 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के आदेश जारी कर दिये गये।
8	आगामी 2 वर्ष में 200 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में से 140 को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जायेगा।	सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा क्रियान्विति की जानी है।
9	इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना में वर्तमान वर्ष से सामान्य वर्ग की की छात्राओं को शामिल करने की बात कही।	बालिका शिक्षा फाउंडेशन, राजस्थान द्वारा इसकी क्रियान्विती की जानी है।
10	विद्यार्थी मित्र, शिक्षा कर्मी, मदरसा शिक्षा सहयोगी, एवं लोक जुम्बिश के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।	विद्यार्थी मित्रों के मानदेय वृद्धि के आदेश जारी किये जा चुके हैं।
11	स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु 'राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान'(सीमेट) को क्रियाशील किया जायेगा	गोनेर में सीमेट के लिये पदों का सृजन किया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के संबंध में कुल 9 व अन्य घोषणायें की गई थीं विभाग द्वारा सभी घोषणाओं की प्रगति की सूचना उपलब्ध करवाई गई।

	घोषणा	प्रगति (05 नवम्बर 2012)
1	मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के हेतु आगामी वर्ष में 300 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया ।	औषधियों की प्राप्ति हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण करके आदेश जारी किए जा चुके है।
2	वर्ष 2012—13 में 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।	25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी हो चुकी है तथा भवन निर्माण के लिए नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है।
3	वर्ष 2012—13 में 100 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेगें।	99 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं उनमें पद सृजन पर स्वीकृति हुई है लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन की जानकारी नहीं दी गई।
4	आगामी 2 वर्षो में 3 हजार नये उप—स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगें।	1500 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं 1500 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर स्वीकृति हो चुकी है भवन निर्माण प्रारम्भ नहीं हो सका है।
5	विभिन्न चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक हजार शय्याओं की वृद्धि की जायेगी।	11 / 7 / 12 को एन.आई.टी. जारी की जा चुकी है।

6	100 शय्याओं वाले सभी चिकित्सा संस्थानों में न्यू–बोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट्स स्थापित की जायेगी।	निविदाये प्राप्त होने के बाद स्वीकृति होना बाकी है। चिकित्सा अधिकारी एवं स्टॉफ के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है।
7	34 जिला अस्पतालो में 30 शैय्या के तथा 12 उप जिला अस्पतालो में, 6 सैटेलाईट अस्पतालों में एंव 68 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 20 शय्याओं के जननी वार्ड स्थापित किए जायेगें।	जिला अस्पतालों के लिये 09.07.12 को उप जिला अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व सैटेलाईट अस्पतालों के लिये 05.07.13 स्वीकृति जारी हो चुकी है।
8	वर्तमान में संचालित 108–एम्बुलेंस की संख्या में 200 तक की बढ़ोतरी की जायेगी।	30/9/12 को स्वीकृति आदेश जारी जारी हो चुके हैं तथा निविदा की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।
9	जोधपुर, बीकानेर, एवं उदयपुर में औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जायेगी।	भवन निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है लेकिन संचालन कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
10	जिला चिकित्सालय बीकानेर एवं मण्डोर चिकित्सालय जोधपुर में कार्डिक केयर युनिट निर्मित की जायेगी।	कार्य स्वीकृति के आदेश जारी हो चुके हैं 04.07.12 से बीकानेर व जोधपुर में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है।
11	सभी आयु वर्ग के बालक– बालिकाओं की डी–वर्मिंग करवाई जायेगी तथा फोलिक ऐसिड की दवा उपलब्ध करवाई जायेगी।	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करके दवाईयां खरीदी तथा आंवटित की गई।
12	राज्य में लिंग परीक्षण पर प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा।	पदों पर नियुक्ति के लिए नियम बनाने के आदेश जारी किए गए है।
13	चिकित्सा विभाग में विभिन्न कैडर्स के 120 अतिरिक्त पद सृजित किये जायेंगें।	विधि सहायक के 34, पुलिस निरिक्षक के 34 व कनिष्ठ लिपिक के 34 पद तथा 18 पद निदेशालय मुख्यालय हेतु स्वीकृत किये गये हैं।
14	गैर–कानूनी रूप से लिंग परीक्षण करने वालों की सूचना देने वाले को एक लाख का पुरस्कार दिया जायेगा।	उक्त योजना के तहत एक व्यक्ति को 30.03.12 को पुरस्कृत किया जा चुका है।
15	नए नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को 1 वर्ष की सेवा के पश्चात् ही वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है	31 मई 2012 को आदेश जारी कर नियम में बदलाव कर दिया गया।
16	NRHM के अन्तर्गत विभिन्न कैडर्स के 21 हजार नियमित पद सृजित करने की घोषणा की गई।	वित्त विभाग ने 20985 पद सृजित करने हेतु स्वीकृति दी है लेकिन नियुक्ति होना बाकी है।
17	प्रदेश के टीएसपी क्षेत्र हेतु ए.एन.एम के एक हजार पद भी सृजित किये जायेंगे।	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) के 1000 पद सृजित करने पर स्वीकृति हो चुकी है लेकिन नियुक्ति होना बाकी है।
18	आगामी वर्षो में स्थापित किये जाने वाले 3 हजार	1500 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) के पद सृजित किये जाने की स्वीकृति जारी की गई है

	उप–स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु ए.एन.एम की भर्ती की जायेगी।	लेकिन नियुक्ति होना अभी बाकी है।
19	आगामी वर्ष दन्त चिकित्सको के 58 रिक्त पदों के साथ ही, 250 नवीन पद सृजित कर भरने की कार्यवाही की जायेगी।	250 चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के पद सृजित किये जाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा भर्ती हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है।
20	नैत्र सहायकों के 210 रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिये प्रस्ताव भिजवाये गये है लेकिन भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ होना बाकी है।
21	वे जिले जहां एक भी फर्टिलिटी क्लिनिक नहीं है, वहां क्लिनिक की स्थापना की जायेगी तथा इन क्लिनिक में बीपीएल दम्पतियों की निःशुल्क चिकित्सा की जायेगी।	31 मई 2012 को स्वीकृति के आदेश जारी हो चुके हैं लेकिन विभाग ने भौतिक प्रगति की सूचना नहीं दी।
22	जी.एन.एम के लिये मैस भत्ते की दर 400 एवं ए.एन.एम के लिये मैस भत्ते की दर 200/रू. प्रतिमाह की जायेगी।	30 अप्रेल 2012 को आदेश जारी किये जा चुके हैं।
23	नवजीवन योजना के समस्त जिलों को मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना का लाभ दिया जायेगा।	31 मई 2012 को नवजीवन योजना के लिये आदेश जारी किये जा चुके है।
24	ए.एन.एम को 400 रूपये प्रतिमाह तथा जी.एन.एम. को 600 रूपये प्रतिमाह से नर्सिग भत्ते का भुगतान किया जायेगा।	30 अप्रेल 2012 को आदेश जारी किये जा चुके हैं।
श्रम कल्याण		
श्रम कल्याण विभाग के संबंध में कुल 3 घोषणायें की गई थीं विभाग द्वारा सभी घोषणाओं की प्रगति की सूचना उपलब्ध करवाई गई।		
	घोषणा	**प्रगति (05 दिसम्बर 2012)**
1	राज्य में Building and other Construction Workers Welfare Board के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों को निःशुल्क साईकिल देने की बात कही गई।	वित्त विभाग साईकिल क्रय करने पर सहमति दे दी है लेकिन साईकिल वितरण प्रारम्भ नहीं हो सका है।
2	अंसगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाऐगी।	अंसगठित श्रमिकों तथा निविदा समिति का चयन किया जा चुका है लेकिन श्रमिकों का बीमा प्रारम्भ नहीं हुआ है
3	1 मई से अकुशल श्रमिक को 147 रू., अर्द्धकुशल श्रमिक को 157 रू., कुशल श्रमिक को 167 रू. तथा उच्च कुशल श्रमिक को 217 रू. प्रतिदिन न्यूनतम मज़दूरी दी जायेगी।	न्यूनतम मजदूरी बढाने के संबंध में 06.08.2012 को आदेश जारी कर दिये गये हैं।
उद्योग		
उद्योग विभाग के संबंध में कुल 3 घोषणायें की गई थीं विभाग द्वारा सभी घोषणाओं की प्रगति की सूचना उपलब्ध करवाई गई।		

	घोषणा	प्रगति (05 दिसम्बर 2012)
1	जोधुर में नेशलन इन्स्टीटयूट ऑफ फैशन टैक्नोलोजी के लिए सरकार आवश्यक भूमि और राशि उपलब्ध करायेगी।	वर्ष 2011—12 में भूमि आवंटन एवं निफ्ट के खाते में निर्माण हेतु 2908 करोड़ आवंटित हो चुके हैं।
2	प्रदेश में दो नगरीय हाट बाजार सीकर एवं अलवर में स्थापित किये जायेंगे।	सीकर व अलवर में भूमि आवंटित हो गई हैं तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका हैं।
3	स्वाबलंबन योजना में ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर 3 हजार युवाओं को लाभान्वित किया जायेगा।	वर्ष 2012—13 में अक्टूबर माह तक 5006 आवेदनों में से 382 को बैंकों द्वारा ऋण दिया जा चुका हैं।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी		
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के संबंध में कुल 7 मुख्य व अन्य घोषणायें की गई थीं विभाग द्वारा सभी घोषणाओं की प्रगति की सूचना उपलब्ध करवाई गई।		
	घोषणा	**प्रगति (01 दिसम्बर 2012)**
1	इस वर्ष 2569 गावों, ढाणियों, 7500 अनुसूचित जाति, 300 अनुसूचित जनजाति एवं 120 अल्पसंख्यक बाहुल्य गॉवो, ढाणियों में पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा।	अब तक 881 ग्राम व ढाणियों, 929 की बस्तियों, 168 अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों, 127 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों एवं 141 अल्पसंख्यक बस्तियों में पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका हैं।
2	शहरी क्षेत्रों में भी 839 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बस्तियों में पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा।	608 अनुसूचित जाति एवं 60 अनुसूचित जनजाति बस्तियों को पेयजल सुविधा दी जा चुका है।
3	शहरी क्षेत्रों में जल वितरण प्रणालियों को सुदृढ करने के विभिन्न कार्यो पर 106 करोड़ रूपये का व्यय किया जायेगा।	कार्ययोजना तैयार करके 45 करोड़ के कार्यो की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी नहीं दी गई है।
4	चालू वर्ष 5300 गॉवों व ढाणियों में हैंडपंपों एवं नलकूपों पर डी—फ्लौरीडेशन यूनिट्स लगा दिये गये हैं तथा आगामी वर्ष में शेष गॉवों व ढाणियों में यूनिट्स में लगाये जायेंगे।	अब तक 2100 डिफ्लोरिडेशन युनिट्स के विरूद्व 433 युनिट्स लगाये जा चुके है।
5	3796 करोड़ रूपये की पेयजल परियोजनायें, आगामी वर्ष में प्रारंभ कर अगले तीन वर्षो में पूर्ण की जायेंगी।	सभी योजनाओं पर आदेशात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। निर्माण कार्य प्रारम्भ होना बाकी है।
6	बाड़मेर, जैसलमेर जिले में 590 करोड़ रू. की पोकरण फलसूंड से 171 गांवों को लाभान्वित किया जायेगा।	कार्यकारी फर्म को कार्योदेश जारी किया जा चुका है तथा योजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
7	218 करोड़ रू. से धवा—समदड़ी परियोजना प्रारंभ कर अगले तीन वर्षो में कार्य पूर्ण किये जायेंगे।	कार्यादेश जारी किया जा चुका है तथा कार्यकारी फर्म द्वारा दिनांक 02.09.12 से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

8	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना में 260 करोड़ रूपये के लागत से आगामी वर्ष एवं अगले तीन वर्षो में कार्य पूर्ण किये जायेंगे।	विभाग द्वारा फर्म का चयन कर लिया गया तथा कार्यकारी फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
9	पाली जिले के तखतगढ़ एवं 111 गॉवों में 88 करोड़ रू. के कार्य आगामी वर्ष एवं अगले तीन वर्षो में पूर्ण किये जायेंगे।	एल एण्ड टी लिमिटेड को कार्यादेश किया जा चुका है। तथा दिनांक 01.09.12 से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
10	बाड़मेर जिले में 160 करोड रू. के लागत से 177 गॉवों हेतु नर्मदा गुडामालानी परियोजना के कार्य पूर्ण किये जायेंगे।	फर्म का चयन किया जा रहा है कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
11	550 करोड़ रू. के लागत से जोधपुर शहर के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य अगले तीन वर्षो में पूर्ण किये जायेंगे।	एम.ई.आई.एल.एम.सी. (जे.वी.) को कार्योदेश किया जा चुका है तथा फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
12	भरतपुर, डीग, नगर, कामा में 162 करोड़ रू. के जल वितरण के कार्य अगले तीन वर्षो में पूर्ण किये जायेंगे।	मैसर्स आई.वी.आर.सी.एल लिमिटेड को कार्योदेश जारी किया जा चुका है तथा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
13	नागौर जिले के मूंडवा, कुचेरा, मेड़ता तथा 327 गॉवों हेतु नागौर लिफ्ट परियोजना में 431 करोड़ रू. के कार्य आगामी तीन वर्षो में पूर्ण किये जायेंगे।	फर्म का चयन करके कार्योदेश किया जा चुका हैं तथा फर्मो द्वारा 15.07.12 से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
14	अजमेर जिले के 113 गॉवों में पीसांगन परियोजना द्वारा 52 करोड़ रू. के कार्य आगामी तीन वर्षो में करवाये जायेंगे।	फर्म का चयन कर लिया गया है। तथा फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
15	अजमेर पुष्कर परियोजना में 80 करोड़ रू. के कार्य आगामी वर्ष में प्रारंभ कर अगले तीन वर्षो में पूर्ण किये जायेंगे।	निविदा प्रक्रिया की जा रही है। कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
16	शहरी जलापूर्ति परियोजना मकराना, नागौर में 21 करोड़ रू. के कार्य अगले तीन वर्षो में पूर्ण किये जायेंगे।	विभाग द्वारा फर्म का चयन कर लिया गया है तथा फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
17	बारां जिले में 52 करोड़ रू. से अंता और 42 गॉवों के लिये नागदा अंता बलदेवपुरा परियोजना के कार्य तीन वर्षो में पूर्ण किये जायेंगे।	विभाग द्वारा फर्म का चयन कर लिया गया है। फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
18	कोटा के 60 गॉवों हेतु 99 करोड़ रू. की बोरवास मंडाना परियोजना में अगले तीन वर्षो में कार्य पूर्ण किये जायेंगे।	जी.के.सी. प्रोजेक्ट लिमिटेड हैदराबाद को कार्यादेश किया गया है तथा फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
19	झालावाड़ के 30 गॉवों हेतु 26 करोड़ रूपये की भीमनी वाटर सप्लाई परियोजना के कार्य अगले तीन वर्षो में पूर्ण किये जायेंगे।	विष्णु प्रकाश पुंगलिया जोधपुर को कार्यादेश किया जा चुका है तथा फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
20	झालावाड़ के डग एवं 32 गॉवों हेतु 28 करोड़ रू. की माधवी वॉटर सफ्लाई परियोजना में अगले तीन वर्षो में कार्य	विभाग द्वारा फर्म का चयन कर लिया गया है। फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

	पूर्ण किये जायेंगे।	
21	बीकानेर जिले के 107 गॉवों हेतु कोलायत गजनेर जल आपूर्ति योजना के द्वितीय भाग का कार्य –65 करोड़ रूपये के कार्य आगामी वर्ष में प्रारंभ कर अगले तीन वर्षो में पूर्ण किये जायेंगे।	फर्म का चयन विभाग की वित्त समिति द्वारा कर लिया गया है मैसर्स द्वारा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जोधपुर को कार्यादेश जारी किया जा चुका है तथा फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
22	बीसलपुर परियोजना में जयपुर के खोनागोरियान व आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति हेतु 21 करोड़ रू. के कार्य अगले तीन वर्षो में पूर्ण किये जायेंगे।	जी.सी.के.सी. प्रोजेक्ट एण्ड वर्क्स लिमिटेड को कार्यादेश हो चुका है। कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया गया है।
23	चरू के रतनगढ़, राजलदेशर, सुजानगढ़, छापर एवं बिदासर एवं 444 गॉवों हेतु रतनगढ़–राजगढ़ आपणी योजना में 325 करोड़ रू. के कार्य अगले तीन वर्षो में पूर्ण किये जायेंगे।	एन.सी.सी. लिमिटेड हैदराबाद को कार्यादेश किया जा चुका है कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
24	झुंझुनू, चूरू के राजगढ़ और 188 गॉवों हेतु राजगढ़–बूंगी परियोजना में 248 करोड़ रू. के कार्य अगले तीन वर्षो में पूर्ण किये जायेंगे।	निविदायें आमंमित्र की जा रहीं हैं तथा कार्य प्रारम्भ होना अभी बाकी है।
25	टोंक के उनियारा एवं 436 गॉवों हेतु बीसलपुर–टोंक–उनियारा परियोजना में 320 करोड़ रू. के कार्य अगले तीन वर्षो में पूर्ण किये जायेंगे।	एल एण्ड टी लिमिटेड को कार्यादेश जारी किया जा चुका है तथा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
26	Japan international cooperation agency (JICA) के सहयोग से नागौर लिफ्ट परियोजना में 617 करोड़ रू. के कार्य आगामी वर्ष में करवाये जायेंगे।	फर्म का चयन करने की प्रक्रिया चल रही है तथा कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
27	भीलवाड़ा को चंबल का पानी उपलब्ध करवाने हेतु 473 करोड़ रू. की लागत से, मेन ट्रांसमिशन लाइन का कार्य आगामी वर्ष में करवाया जायेगा।	एन.सी.सी. लिमिटेड हैदराबार को कार्यादेश किया जा चुका है तथा फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
28	चंबल से बूंदी को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 80 करोड़ रू. की लागत से ट्रांसमिशन पाइपलाइन स्थापित करने का कार्य आगामी वर्ष में प्रारंभ करवाया जायेगा।	निविदायें आमंमित्र की जा रहीं हैं तथा कार्य प्रारम्भ होना अभी बाकी है।
29	नागौर में नावां तहसील के 72 गॉवों एवं ढाणियों को बीसलपुर बांध से पेयजल दिलवाने हेतु 125 करोड़ रू. की लागत से आगामी 3 वर्षो में कार्य पूर्ण करवाये जायेंगे।	फर्म का चयन करने की प्रक्रिया चल रही है तथा कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
30	अलवार जिले में चंबल नदी से जलापूर्ति करने के उद्देश्य से फिज़िबिलिटी सर्वे करवाया जायेगा।	फर्म पी.डी. कोर लिमिटेड द्वारा माह सितम्बर 2012 से कार्य शुरू कर दिया गया है।
31	अजमेर दरगाह के आस पास कुल 28 करोड रू. के विभिन्न निर्माण एवं सुदृढीकरण के कार्य करवाये जायेंगे।	दरगाह में कायड विश्राम स्थल को 31.05.2012 को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है शेष निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना अभी बाकी है।

32	सीकर के 3 कस्बों और 283 गॉवों में नाबार्ड के सहयोग से 832 करोड़ रू. से फतेहपुर–लक्ष्मणगढ़ पेयजल योजना के कार्य आगामी वर्ष में करवाये जायेंगे।	एल एण्ड टी लिमिटेड को कार्यादेश जारी किया जा चुका है लेकिन कार्य प्रारम्भ किया जाना बाकी है।
33	बाड़मेर लिफ्ट योजना मे 125 करोड़ रू. से बाड़मेर आउटलेट से 68 गॉवों में पेयजल योजना के कार्य आगामी वर्ष में करवाये जायेंगे।	परियोजना की तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है तथा कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
34	बीसलपुर दूदू परियोजना में सूरजपुरा में 90 करोड़ रू. की लागत से फिल्टर फ्लांट का निर्माण कार्य करवाया जायेगा।	कार्य की निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं तथा कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
35	नर्मदा से जालोर शहर के लिये 58 करोड़ रू. की पेयजल परियोजना का कार्य आगामी वर्ष में करवाया जायेगा।	कार्य की निविदा आमंत्रित की जा रही है तथा कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
36	इंदिरा गॉधी नहर से माणकलाव–दांतिवाड़ा परियोजना में 74 करोड़ रू. की लागत से पीपाड़ शहर एवं 32 गॉवों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु कार्य करवाये जायेंगे।	मैसर्स विष्णु प्रकाश पुंगलिया जोधपुर को कार्यादेश किया गया है तथा फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
37	आगामी वर्ष 11 करोड़ रू. से गढ़ी–सेमलिया, मोटी बस्सी कुण्ड, तलवाड़ा की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन का कार्य करवाया जायेगा।	सभी योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है लेकिन कार्य प्रारम्भ किया जाना अभी बाकी है।
जल संसाधन		
जल संसाधन विभाग से संबंधित कुल 9 मुख्य एवं अन्य घोषणाएं की गईं विभाग द्वारा सभी घोषणाओं की प्रगति की जानकारी उपलब्ध करवाई गई।		
	घोषणा	**प्रगति (01 दिसम्बर 2012)**
1	इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं सिंचाई परियोजना हेतु 1086 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया है।	अक्टूबर, 2012 तक विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर कुल 302.09 करोड़ रू. व्यय किये जा चुके है।
2	चित्तौड़गढ की जल सागर, उदयपुर की घोड़ा खोज भरतपुर की एक्सटेंशन ऑफ अबार सोगर तथा सिरोही की आखेलाव मानसरोवर सिंचाई परियाजनाएं पूर्ण की जायेंगी।	जल सागर परियोजना पर 26000 लाख रू. के विरूद्ध 23.37 लाख रू. व्यय किये गये है। घोडा खोज सिंचाई परियोजना में बांध का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं नहर का कार्य प्रगति पर है। एक्सटेंशन ऑफ अबार सागर लघु सिंचाई परियोजना को पूर्ण कर लिया गया हैं। आखेलाव मानसरोवर लघु सिंचाई परियोजना का कार्य प्रगति पर है।
3	आगामी वर्ष 6 जिलों में सात नई लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ की जायेंगी।	सभी 7 परियोजनाओं का तकमीना तैयार किया जा रहा है परियोजना का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

4	इन 4 पूर्ण एवं 7 प्रस्तावित परियाजनाओं से लगभग 3700 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।	अबार सोगर सिंचाई परियोजना से अब तक 1998 हैक्ट. क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
5	कोटा जिले की सांगोद तहसील में किशोरपुरा एवं आवां एनिकट के निर्माण कार्य आगामी वर्ष में किये जायेंगे।	एनीकटों के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके है लेकिन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
6	भैंसा सिंह जिला सिरोही, भंवर सेमला जिला प्रतापगढ़ ल्हासी जिला बारां, कनवाड़ा तथा पीपलाद जिला झालावाड़ तथा कोटा में सिंचाई परियोजनायओं का कार्य कराया जायेगा।	भैंसा सिंह लघु सिंचाई परियोजना में 500.00 लाख रू. के विरूद्ध 190.00 लाख रू. व्यय हो चुके हैं। भंवर सेमला लघु सिंचाई परियोजना में 182.31 लाख रू. व्यय किये जा चुके हैं। ल्हासी सिंचाई परियोजना में 2200 लाख रू. के विरूद्ध 1143.80 लाख रू. व्यय किये गये है। कनवाडा लघु सिंचाई परियोजना में 300.01 लाख रू. के विरूद्ध 57 लाख रू. व्यय किये गये है। पीपलाद सिंचाई परियोजना में 600 लाख रू. के विरूद्ध 90.88 लाख रू. व्यय किये गये है। तकली मध्यम सिंचाई परियोजना में 2000 लाख रू. के विरूद्ध 32.28 लाख रू. व्यय किये गये है।
7	घाटोल की खमेरा नहर से 16 गांवों के 7000 हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई कार्य करवाया जायेगा।	कार्य आदेश जारी हो गये हैं कार्य की लागत 2.00 करोड़ रू. है। कार्य प्रारम्भ होना अभी बाकी है।
8	डूंगरपुर जिले की सोम कमला अंबा परियोजना के बांध एवं नहर का आधुनिकीकरण करवाया जायेगा।	निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश जारी किय गये है लेकिन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
9	गंग नहर के आधुनिक करण का कार्य करवाया जायेगा।	गंग नहर आधुनिकरण का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मुख्य फीडर की लाईनिंग का कार्य शेष है।
10	गंगानगर शहर से गुजरने वाली ए–माइनर को कवर करने का कार्य करवाया जायेगा।	निविदायें आमंत्रित कर कार्यादेश जारी किया जा चुका है लेकिन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
11	कुम्भाराम आर्य लिफ्ट में इंदिरा गांधी मुख्य नहर पर क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण करवाया जायेगा।	निविदायें स्वीकृत हो चुकी है एवं कार्यादेश दिये जा चुके है लेकिन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
12	श्रीगंगानगर की एटा सिंगासर लघु सिंचाई परियोजना में 1966 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु निर्माण करवाया जायेगा।	वर्ममान में सर्वे कार्य किया जा रहा है लेकिन निर्माण कार्य प्रारम्भ होना अभी बाकी है।
13	विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 28966 हैक्ट्रेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।	अब तक गंग नहर में 506 हैक्ट., नर्मदा नहर में 4000 हैक्ट. तथा लघु सिंचाई परियोजना में 155 हैक्ट. सिंचित क्षेत्र खोला जा चुका है।
14	नर्मदा नहर परियोजना के अन्तर्गत 11000 हैक्ट्रयर सिंचित	अब तक 4000 हैक्ट. सिंचित क्षेत्र का विस्तार किया

	क्षेत्र का विस्तार एवं परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में फव्वारा पद्वति से 50000 हैक्ट्रयर क्षेत्र कर विस्तार किया जाएगा।	गया है तथा फव्वारा पद्धति में 10000 हैक्ट. क्षेत्र का विस्तार किया गया है।
15	बांसवाड़ा में हरिदेव जोशी नहर पर सुद्ढ़ीकरण एवं सब–माइनर्स के निर्माण का कार्य करवाया जायेगा।	कार्य आदेश किये जा चुके हैं लेकिन कार्य की प्रगति की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गई।
16	बांरा जिले की परवन वृहद सिंचाई एवं पेयजल परियोजना में निर्माण कार्य करवाये जायेंगे।	परियोजना में वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति अभी बाकी है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
17	बारां जिले में परवन वृहद सिंचाई एवं पेयजल परियोजना से 313 गांवों के 131400 हैक्ट्रेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा तथा 820 गांवों में पेयजल की सुविधा प्राप्त हागी।	परियोजना का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।
18	डूंगरपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर 7 एनिकटों का 12 करोड़ रू. की लागत से निर्माण करवाया जायेगा।	सभी एनीकटों के लिये निविदाएं ली जा रही हैं निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
19	डूंगरपुर जिले में वारन्दा लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण से 300 हैक्ट्रेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।	कार्य की स्वीकृति हो गई है लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
20	माही परियोजना से गमेंलों माइनर के निर्माण से डूंगरपुर के 165 हैक्ट्रेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।	निविदायें आमंत्रित कर कार्य आदेश कर दिये गये है। कार्य प्रगति की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गई।
21	धौलपुर जिले के बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में 23 करोड़ रूपये की लागत से 4 एनिकटों को निर्माण करवाना।	चारों एनीकटों 2513.00 लाख रू. की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
22	डूंगरपुर जिले के आसपुर क्षेत्र में नहर को कवर करवाया जायेगा।	निविदायें आमंत्रित कर कार्य आदेश जारी हो गये है कार्य में प्रगति की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गई।

स्रोत – उपरोक्त विवरण विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है।

घोषणाऐं जो पूरी नहीं हुई या जिनकी प्रगति की जानकारी नहीं

	नगरीय विकास विभाग
1	जयपुर में मेट्रो रेल का प्रथम चरण का कार्य जून 2013 में पूर्ण होने तथा रेल परिचालन प्रारम्भ होने की बात कही गई।
2	शहरी स्थानीय निकायों को 350 करोड़ रू. की राशि अनटाईड फंड के रूप में देने की बात कही गई जिस राशि से अनुसूचति जात, जनजाति एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य कच्ची बस्तियों में आधारभूत सुविधााओं के विकास की बात कही गई।
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
1	कुष्ठ रोग से मुक्त विशेष योग्यजनों को बीपीएल के अनुरूप 2 रू. प्रतिकिलो की दर से गेंहू दिया जायेगा।
	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
1	उदयपुर में राजीव गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई।
	वन विभाग
1	राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रारम्भ करने की बात कही गई।
	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
1	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढाने के लिये मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ करने की बात कही गई।
2	महानरेगा अंतर्गत जलस्रोतों के रखरखाव एवं जलग्रहण के कार्य प्राथमिकता से लिये जायेंगे।
	कृषि
1	राजफैड के माध्यम से इस वर्ष 2 लाख 50 हजार मैट्रिक टन डीएपी, 2 लाख मैट्रिक टन एसएसपी, 50 हजार मैट्रिक टन कॉप्लेक्स उर्वरक एवं 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया का भंडारण किया जायेगा।
	राज्य में कृषकों को अनुदान देकर 2 हजार 200 सौर उर्जा आधारित पंपसेट स्थापित किये जायेंगे।
	अलवर जिले में 40 हैक्टेयर क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर पार्क विकसित करने की बात कही गई।
	आगामी वर्ष में बूंद बूंद सिंचाई की स्थापना हेतु 90 प्रतिशत अनुदान देने के लिये 140 करोड़ रू. एवं फर्टीगेशन आधारित ड्रिप सिंचाई के लिये 25 करोड रू. का प्रावधान रखा जायेगा।
	पशुपालन
	राजस्थान राज्य डेयरी फैडरेशन के माध्यम से पाली में केटल फीड प्लांट एवं जयपुर में पाउडर मिल्क प्लांट का निर्माण करवाने की बात कही गई।

स्रोत – उपरोक्त विवरण विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है।